

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्यों छिड़ा विवाद?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दखिल करने के बाद विवाद में फंस गई है। बीजेपी पर 'हिंदु विरोधी' होने का आरोप लगाते हुए, स्क्रीनशॉट वायरस हुए, एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया सरकार का हलफनामा 1983 का रामजी महाजन आयोग रिपोर्ट का भी सहारा ले रहा है। हालाँकि सरकार ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वायरल पोस्ट में ऐतिहासिक संदर्भों का जिक्र किया गया, वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दिये गया हलफनामा सभी सामान्य जाति के लोगों के लिए एक चेतावनी है। हमेशा हिंदुओं को एकजुट करने का दावा करती, वालो पार्टी अब एकजुट नहीं हिंदू धर्म को अत्यंत, शांति और बुद्धि का प्रतीक बना रही है। आरोप लगाए गए कि हलफनामे के कथित अंशों में लगभग 80 फीसदी हिंदुओं के पिछड़े वर्ग के लिए रामायण और मनुस्मृति जैसे हिंदू धर्मग्रंथों को दोषी ठहराया गया। इतना ही नहीं, विस्तर पर वायरल स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि कई अन्य अजीबोगरीब दावे भी इसमें शामिल थे। एक स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि रामायण में ऋषि शंबूक की हत्या को जातिगत उन्नीड़न के उदाहरण के रूप में पेश किया गया। एक अन्य स्क्रीनशॉट में तुलना दावा किया गया था कि मनुस्मृति शूद्रों की वृहदा जानवरों से कफ के अंडे अमानवीय बनाती है। साथ ही उच्च-जाति के

प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए हिंदू समाज को सदियों तक जानबूझकर विभाजित रखा गया था। इन दावों को लेकर सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और विवादास्पद अंशों से खुद को पूरी तरह अलग बताया।

विवाद के बाद एमपी सरकार ने क्या कहा?

सूखे की सरकार ने कहा कि संज्ञान में यह ध्यान आया है कि शराही तत्वों की ओर से सोसायल मीडिया पर यह कहते हुए कुछ कंटेंट वायरल किया जा रहा है कि वह टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश मध्य प्रदेश शासन के ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण के हलफनामे का भाग है। शासन ने कंटेंट का गंभीरता से परीक्षण किया है। ये टिप्पणियाँ पूरी तौर पर असत्य, मिथ्या और भ्रामक हैं। ये दुष्प्रचार की भावना से किया गया है। वह स्पष्ट किया जाता है कि वायरल की जा रही सामग्री मध्य प्रदेश सरकार के हलफनामे में उल्लेखित नहीं है और ना ही राज्य की किसी घोषित या स्वीकृत नीति अथवा निर्णय का भाग है। उसने कहा कि सामग्री मध्य प्रदेश राज्य पिछड़े वर्गों के आयोग के अध्यक्ष रामजी महाजन की ओर से पेश अंतिम रिपोर्ट (भाग-1) का हिस्सा है। आयोग का गठन 17 नवंबर 1980 को किया गया था। आयोग ने 22 दिसंबर 1983 को अपनी अंतिम रिपोर्ट तलाकालीन राज्य शासन को भेजी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधित मामले में राज्य पिछड़े वर्गों आयोग की रिपोर्ट पेश की है। इन रिपोर्ट में महाजन आयोग की

रिपोर्ट के साथ-साथ 1994 से 2011 तक के वार्षिक रिपोर्ट व साल 2022 की राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट भी शामिल है।

**M P सरकार ने हलफनामे में क्या दिया
तर्क?**

मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़कर 27 फीसदी करने के अपने निर्णय का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछड़े समुदाय की की जनसंख्या का 85 फीसदी से अधिक है और गंधी रूप से वर्णित हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 8 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई करेगा. 23 सितंबर को दायर अपीलनामों में राज्य ने 2011 की जनगणना का हलफा दिया, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति (एससी) 15.6%, अनुसूचित जनजाति (एसटी) 21.1% और ओबीसी 51% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओबीसी आयोग की 2022 की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि अकेले ओबीसी राज्य की आधी से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के अनुसार, वर्तमान समूह मिलकर मध्य प्रदेश की 87 फीसदी से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार ने कहा कि ओबीसी को पहले केवल 14 फीसदी आरक्षण तक सीमित रखा गया था, जो जनसंख्या के लिए राज से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए पूरी तरह से अनुप्राणीत नहीं था। सरकार ने तर्क दिया कि 27 फीसदी तक की वृद्धि न केवल उचित है, बल्कि एक संवैधानिक रूप से

जरूरी सुधार करने वाला कदम भी है। यह हफ्तेपानामा मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 4 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया था, जिसे 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके चलते राज्य की सेवाओं में सभी पदों पर ओबीसी के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़कर 27 फीसदी बना दिया गया है।

मध्य प्रदेश में कितना हो जाएगा
आरक्षण?

साल 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एकल अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें राज्य को 14 फीसदी से अधिक ओबीसी आरक्षण देने से रोक दिया गया और दिसंबर 2019 के अनियम 73 पर रोक लगा दी गई। 2024 में याचिकाएं सुप्रीम कोर्टों में दांभसफर कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द नहीं किया और मामले की ऑर्म सुनवाई अक्टूबर 2025 के लिए निर्धारित कर दी. चूंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों को 16 फीसदी और अनुसूचित जनजातियों को 20 फीसदी आरक्षण प्राप्त है, इसलिए ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी करने से आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अधिक हो जाएगा. 10 फीसदी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) को के साथ कुल आरक्षण 73 फीसदी हो जाएगा।

वायुसेना प्रमुख का ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बड़ा खुलासा- पाकिस्तान के 6 से 7 जेट मार गिराए...

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नहीं बताया कि इतने लंबी दूरी पर कौन सा पाकिस्तानी उपकरण गिराया गया और किस भारतीय मिसाइल सिस्टम ने यह हमला किया। लेकिन माना जा रहा है कि यह रूस से खरीदी गई अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली हो सकती है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से अधिक है।

वायु सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता और असर के कारण यह इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'हमने एक ही रात में सटीक हमला किया, कम से कम नुकसान पहुंचाया और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह 1971 के बाद का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है जिसे सार्वजनिक रूप से बताया गया है।' उन्होंने सेना, नौसेना और वायु सेना की संयुक्त योजना और क्रियान्वयन की भी सराहना की। उन्होंने कहा, 'हमने ऑपरेशन सिंदूर में साबित किया कि हम निशानेबाज,

अजेय और सटीक है।" फर्जी खबरों और मीडिया के रोल पर भी उन्होंने चर्चा की। सिंह ने कहा, "ऑपरेशन के दौरान लतफत ज़ानकारी फैलाई गई, लेकिन हमारे मीडिया ने सेना का खूब सहयोग किया। जब सैनिक लड़ रहे होते हैं तो जनता का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, और मीडिया ने इसका ध्यान रखा।" आगे की तैयारी के बारे में बात करते हुए एयर चीफ ने कहा कि भविष्य के युद्ध पहले जैसे नहीं होंगे। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा और सभी सैन्य सेवाओं तथा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए बताया कि एलसीएम Mk1A के इंजन दिए गए हैं और LCA Mk2 और आईडिए मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (IMRH) के प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। कई रेडार और सिस्टम पर भी काम हो रहा है। सिंह ने कहा, "हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जहाँ जरूरत होगी वहाँ रणनीतिक तकनीक भी हासिल करेंगे।" अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त अभ्यासों की भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि UAE, मिस्र, फ्रांस और सिंगापुर जैसे देशों के साथ सफल अभ्यास हुए हैं और विदेशी कामांड भी इसे आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं।

‘हमारे पी.एम. झूठ बोलते हैं’, आजादी की लड़ाई में RSS की भूमिका पर ओवैसी ने उठाए सवाल, बोले- हेडगेवार ने तो

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हेराराबाद- एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उनकी जानकारी के अनुसार आरएसएस के गठन के बाद इसके किसी भी सदस्य ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की अहुति नहीं दी और न ही जेलों को। ओवैसी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका की सराहना करने के बाद आई है। यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार की जीवन की कहाला देते हुए दावा किया कि हेडगेवार ने 1930 में दांडी मार्च में हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे, तबकि स्वतंत्रता सेनानियों को बाद में संघ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि हेडगेवार का इरादा स्वतंत्रता संग्राम में वास्तविक भागीदारी का



नहीं था। ओवेसी ने कहा, "मैं इस दावे से हैरान हूँ कि आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी को लंबे-लंबे भाषण देने की आदत है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आरएसएस के किसी भी सदस्य ने इसके गठन के बाद न तो आजादी की लड़ाई में अपनी जान दी और न ही जेल गए।" उन्होंने दावा किया कि ब्रिटिश अभिलेखागार में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया और न ही उनसे कोई खतरा था।

ओवैसी ने कहा, "इसके अलावा,

मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारत के लोग कभी अपमान
बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुतिन का बड़ा बयान, यूरोप को वॉर्निंग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रूस और यूरोप के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ़ कहा कि यदि यूरोप ने रूस को उकसाने की कोशिश की तो उसका जवाब तुरंत और बेहद घातक होगा। साथ ही उन्होंने रूस-यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश करने के लिए भारत की तारीफ की। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा, मैं पीएम मोदी को जानता हूँ, भारत के लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, रूस भारत और चीन जैसे देशों का आभारी है, जिन्होंने ब्रिक्स की स्थापना की। ये ऐसे देश हैं जो कभी-कभी पक्ष लेते से इनकार करते हैं और वास्तव में एक न्यायपूर्ण विश्व बनाने की आकांक्षा रखते हैं।

दक्षिण रूस में आयोजित एक समारोह में
पुतिन ने कहा, हम यूरोप के बहुत सैनीकरण
पर बागीकी से नकार खा रहे हैं। रूस की और से
जवाबी कदम उठाने में वक़्त नहीं लगेगा। और
यह प्रतिक्रिया बहुत गंभीर होगी। पुतिन ने साफ
फिरा कि रूस कमजोरी या अनिर्णय का
परिचय कभी नहीं देगा। हालाँकि उन्होंने यह भी
जोड़ा कि रूस का नाटो गठबंधन पर हमला
करने का कोई इशारा नहीं है। उन्होंने तंज कसते
हुए कहा, "अगर किसी को अभी भी हमारे
साथ सैन्य प्रतियोगिता करने का मन है, तो उन्हें
कोशिश कर लेने दें। रूस ने सदियों से यह
साक्षात् किया है कि उसमाके का जवाब तुरंत
और सख्ती से दिया जाता है।

शांति से सोइए, आराम कीजिए
राष्ट्रपति पुतिन ने विशेष रूप से जर्मनी का
नाम लेते हुए कहा कि वह यूरोप में सबसे

शक्तिशाली सेना बनाने का सपना देख रहा है।
उन्होंने यूरोपीय नेताओं पर हिस्टोरिया फैलाने का
आरोप लगाया। यूरोप की एकजुट अभिजात्य
जमात लगातार युद्ध की आशंका का माहौल
बना रही है। वे बार-बार कहते हैं कि रूस से
जंग दरवाजे पर खड़ी है। यह एक तरह की
बकवास है, जिसे वे मंत्र की तरह दोहराते रहते
हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मानना ​​रहने
है कि रूस का भी नाटो के किसी सदस्य देश पर
हमला करेगा। सचमुच, मैं सिर्फ यही कहना
चाहता हूँ—शांति से सांश, आराम कीजिए और
अपने घर की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। जरा
देखिए कि यूरोपीय शहरों की सड़कों पर क्या
हो रहा है।

रूस-यूरोप टकराव- शीत युद्ध से आगे
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने पश्चिमी मीडिया की शीत युद्ध जैसी तुलना को खारिज किया। उन्होंने कहा, यह शीत युद्ध नहीं है। यहां काफी पहले से उंड नहीं, बल्कि आग लगी हुई है। हम पहले से ही एक नए तहक के संघर्ष में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ और नारो, रूस पर झुट्टे आरोप लगाकर अपने विचारल शक्का बजट को सही ढर्रना चाहेते हैं। +उन्के बयानो दो चीजो बताते हैं। पहला, वाकतसावे की एक फूक खोजो तैयार कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें अपने सैन्य बजट

को जायज ठहराने का बहाना चाहिए।

डूबे घटनाएं और बढ़ती चिंताएं

पिछले दिनों डेनमार्क में झूठ घटनाओं और एस्टोनिया व पोलैंड में कथित रूसी हवाई उल्लंघनों ने इस डर को गहरा कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध की आग सीमाओं से बाहर फैल सकती है। हालाँकि पुतिन ने इन चिंताओं को 'अफवाह और प्रोपेगेंडा' बताते हुए खारिज किया. उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों का मकसद अपने सैन्य खर्च को जायज ठहराना है।

अमेरिका और रूस में तनाव

सिर्फ दो महीने पहले अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बावजूद शांति की उम्मीदें अब और धुंधली होती दिख रही हैं। रूसी सेना यूक्रेन में लगातार बढ़त बना रही है, वहीं रूसी ड्रोन के नाटो हवाई क्षेत्र में दाखिल होने की रिपोर्टें भी आई हैं। इस बीच, अमेरिका अब रूस के भीतर गहरे हमले करने पर विचार कर रहा है।

भारत की तारीफ

अपने स्वतंत्रता में पतित न भारत की
उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व राजनीति में
आज का संतुलित दृष्टिकोण काबिले तारीफ है।
उन्होंने कहा, भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश-
नीति से यह दिखाया है कि बड़े लोकतांत्रिक
राष्ट्र भी दबावों के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों
को संवर्धित रख सकते हैं। रूस भारत के एक
भरोसेमंद साझेदार मानता है। पुतिन ने यह भी
कहा कि भारत ने हमेशा संवाद, शांति और
कूटनीति पर जोर दिया है, जो मौजूदा समय में
बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत के ऊर्जा-
सहयोग और रणनीतिक संतुलन की भी
सराहना की।

दोकटी, हल्दी की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अधिकारी जाम समाप्त करने के लिए बार-बार आग्रह कर रहे थे। लोगों का यह कहना था कि हर साल के भाँति दशहरा मेला तो देखते हुए बैरिया मे नो एट्री क्यों नहीं लगाया गया इसका जवाब पुलिस वालों के पास नहीं था। अधिकारी बार-बार जाम समाप्त करने का आग्रह आक्रोशित लोगों से कर रही थी कि तुम लोग प्रशासन को बात नहीं सुन रहे थे। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण सड़क पर जमे हुए थे। प्रशासन उनके मान-मौल में लगा हुआ था। सड़क जाम कर रहे लोगों ने दोनों मृतकों के आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपए की सहायता व गाड़ी मालिक को मौके पर तुरंत बुलाने की मांग कर रहे थे। वहीं सड़क जाम के कारण एनएच 31 पर दोनों तरफ तीन से चार किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है।

